एससीआर में निजी निवेश को करें प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: यूपी-एससीआर (स्टेट कैपिटल रीजन) परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीपीआर की प्रक्रिया में अब और विलंब न करने की हिदायत दी। 27,826 वर्ग किमी क्षेत्रफल की यूपी-एससीआर परियोजना के तहत लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिले हैं। मुख्यमंत्री ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप(पीपीपी) माडल आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने, प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष आवासीय योजनाएं संचालित करने और ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणीकरण, सोलर रूफटाप सिस्टम, रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन को अनिवार्य शहरी मानक के रूप में लागू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यूपी आवास एप और रेरा पोर्टल को और अधिक सुगम व पारदर्शी बनाए जाने पर भी बल दिया।

प्रस्तावित भवन उपविधि पर 30 अप्रैल तक 1153 सुझाव व आपत्तियां दर्ज कराई गईं हैं। इन्हें निस्तारित कर उपविधि को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत क्रियाशील परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए संशोधित गाइडलाइन भी जल्द जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण-नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से लांच करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में तेजी से कार्य किए जाएं और सभी परियोजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

जीआइएस आधारित महायोजना संरचना के तहत प्रदेश के 59 नगरों की तैयार की जा रही महायोजनाओं में से 42 के ही अनुमोदित किए जाने पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि झांसी, मैनपुरी, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ एवं बहराइच के अनुमोदन की प्रक्रिया इसी माह पूरी की जाए।

बढ़ेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण का दायरा

राजधानी में बढ़ती आबादी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के दायरे को बढ़ाया जाए। एलडीए के सीमा विस्तार से जहां सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा, वहीं बढ़ती आवासीय मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। बैठक में योगी ने गोमतीनगर स्थित जेपीएनआइसी को यथाशीघ्र एलडीए को हस्तांतरित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मेट्रो परियोजना के तहत चारबाग से बसंतकुंज तक 11.165 किलोमीटर की मेट्रो लाइन का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। इंटरनेशनल एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 900 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ में 32.50 एकड़ भूमि पर बनाए जा रहे कन्वेंशन सेंटर के काम को अधिकतम दो वर्ष में पूरा किया जाए।

उन्होंने विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश देते हुए कहा कि मानचित्र से जुड़े मामलों में बार-बार आपत्ति लगाने के बजाय सरल रूप देते हुए एक ही बार में निस्तारित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि कानपुर मेट्रो के मोतीझील से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक 6.7 किमी. लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण पूरा हो चुका है। कारीडोर एक व दो का कार्य इस वर्ष के अंत तक हो पूरा जाएगा। आगरा मेट्रो के प्रथम कारिडोर को इस वर्ष दिसंबर तक जबकि द्वितीय कारिडोर का कार्य अगले वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें
www.jagran.com पर पढ़ें